



निबंधन संख्या पी०टी०-४०

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 32 पटना, बुधवार, 18 श्रावण 1939 (श०)
9 अगस्त 2017 (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
	पृष्ठ	
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०ए०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9—विज्ञापन
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
		पूरक
		पूरक-क
		3-3
		4-11

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

25 जुलाई 2017

सं० 2/प1-01/2011-106—एतद् द्वारा कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा पद्म उपाधियों के लिए अनुशंसा समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| 2. अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| 3. डॉ० रामवचन राय, वरिष्ठ साहित्यकार | — | सदस्य |
| 4. श्रीमती बऊआ देवी, वरिष्ठ चित्रकार | — | सदस्य |
| 5. श्री हसन इमाम, रंगकर्मी | — | सदस्य |
| 6. निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय | — | सदस्य |
| 7. निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय | — | सदस्य सचिव |
| 8. निदेशक, संग्रहालय निदेशालय | — | सदस्य |
| 9. निदेशक, पुरातत्व निदेशालय | — | सदस्य |
| 10. उप निदेशक (कला एवं संस्कृति) | — | सदस्य |
2. उक्त अधिसूचना अगले आदेश तक के लिए मान्य होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
तारानन्द महतो वियोगी, उप—सचिव।

निगरानी विभाग,
सूचना भवना, पटना

अधिसूचना

31 जुलाई 2017

सं० 4/निग० जल संसाधन 20/17-3185 (अनु०)—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 17/मुक०-07-26/2015-1126 दिनांक 18.07.2017 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में नवादा जिलान्तर्गत फुलवरिया जलाशय योजना के पंचाटियों को जयघोष राशि का भुगतान में हुई कतिपय अनियमितताओं में संलग्न दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नगर थाना, नवादा में दर्ज प्राथमिकी नगर कांड संख्या-586/16 के अग्रतर अनुसंधान का प्रभाव विशेष निगरानी इकाई, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

अतः तत्काल प्रभाव से नगर थाना नवादा कांड संख्या-586/16 के अधिग्रहण एवं अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए विशेष निगरानी इकाई, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं
और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No 930—I, **SRIJAN**, S/o Shri Sanjay Kumar Tripathi, R/o D/95, Police Colony, P.O- Anisabad, P.S- Gardanibagh, Dist- Patna, Pin Code-800002 (Bihar) declare vide Affidavit no 10214 Dated 27/05/17 shall be known and called as **Srijan Tripathi**.

SRIJAN.

सं० 941—मैं, राजेश कुमार, पिता—दामोदर पोद्दार पंजाबी कॉलोनी रोड नं० 1 धरमपुर जिला समस्तीपुर बिहार यह घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र प्रियांशु का नाम संशोधित होकर प्रियांशु कुमार हो गया है शपथ पत्र संख्या 1809 दिनांक 14.07.2017।

राजेश कुमार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 08/आरोप-01-26/2016, सां०प्र०-8806
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
18 जुलाई 2017

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री वजैनुद्दीन अंसारी, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-493/11) के विरुद्ध अपर समाहर्ता, गया के पदस्थापन काल में विभागीय कार्यवाही (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2773 दिनांक 26.02.2014 द्वारा संस्थित) के प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप उजागर हुए हैं। (यथा अनुलग्नक आरोप, प्रपत्र 'क' में वर्णित)।

2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्रों एवं बी०टी० एक्ट-1973 के प्रावधानों के प्रतिकूल भूमि लगान निर्धारण में अनियमितता के आरोपों की जाँच हेतु श्री विजय कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नगर अंचल, गया के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में श्री अंसारी ने सरकार के हित की अनदेखी करते हुए आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर अपनी सहमति संबंधी मंतव्य दे दिया। जिससे जिला स्तर पर की गयी जाँच से उद्भूत भूमि लगान निर्धारण में गम्भीर अनियमितता संबंधी गठित आरोपों को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं बताया जा सका। एतद्संबंधी जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन में अनियमितता के लिए विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3857 दिनांक 29.03.2017 द्वारा श्री अंसारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी उक्त स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सका जिससे मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई बाधित रही।

3. अतएव यह निर्णय लिया जाता है कि श्री वजैनुद्दीन अंसारी के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की वृहद जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, **आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया** एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, गया द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे।

4. श्री अंसारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-123/2015, सां०प्र०-8758

संकल्प

18 जुलाई 2017

श्री उपेन्द्र झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-265/08 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी अनुमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में भूमि लगान निर्धारण में अनियमितता, निलाम पत्र वाद के निष्पादन में शिथिलता बरतने इत्यादि प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-5033 दिनांक 01.06.2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री झा के दिनांक 31.07.2011 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप संकल्प ज्ञापांक-4967 दिनांक 03.04.2012 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी०) के तहत सम्पूरित किया गया। कालान्तर में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी के लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरांत आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर संकल्प ज्ञापांक-6662 दिनांक 25.04.2013 द्वारा श्री झा के पेंशन से 5 प्रतिशत कटौती का निर्णय संसूचित किया गया।

उक्त पेंशन कटौती आदेश के विरुद्ध श्री झा ने पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की। एतदसंबंधी सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-13629/13 में दिनांक 07.12.2015 को न्यायादेश पारित हुआ जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

"In this view of the matter, the impugned order dated 25-04-13, as contained in Annexure-12, passed by the disciplinary authority is not sustainable in law and is accordingly set aside. In the result, this writ application is allowed to the extent indicated above."

उक्त न्यायादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एल०पी०ए० दायर करने का निर्णय लिया गया। विभागीय प्रस्ताव के आलोक में विधि विभाग की सहमति के उपरांत एल०पी०ए० सं०-1127/16 दायर हुआ। इसी बीच झा ने रीट याचिका (सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-13629/13) में पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं किये जाने के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में अवमाननावाद दायर कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत दिनांक 11.05.2017 को आदेश पारित करते हुए एल०पी०ए० सं०-1127/16 को खारिज कर दिया गया। श्री झा ने संदर्भित एल०पी०ए० में पारित न्यायादेश के आलोक में पेंशन कटौती संबंधी आदेश वापस लेने हेतु एक अभ्यावेदन (दिनांक 25.05.2017) विभाग में समर्पित किया।

सम्यक् विचारोपरांत एल०पी०ए० सं०-1127/16 में पारित न्यायादेश (दिनांक 11.05.2017) के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6662 दिनांक 25.04.2013 (श्री झा के पेंशन से 5 प्रतिशत पेंशन से कटौती संबंधी आदेश) वापस लिया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-13/2015, सां०प्र०-8552

संकल्प

13 जुलाई 2017

श्री ओम प्रकाश, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-492/11 (सम्प्रति अन्य आरोपों के लिए निलंबित) के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम, रोहतास के पदस्थापन काल में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित करने के कृत्य के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2014 को पारित आदेश (सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-21003/12 अभयचन्द्र मिश्र बनाम राज्य सरकार) के अनुपालन में अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ की गयी। इस क्रम में प्राप्त आरोप, प्रपत्र 'क' (जिला पदाधिकारी, रोहतास का पत्रांक-850, दिनांक 16.08.2014) की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-12261, दिनांक 03.09.2014 द्वारा श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः विभागीय पत्रांक-17663, दिनांक 23.12.2014 द्वारा स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् उन्होंने कतिपय तथ्यों से आच्छादित एक आवेदन समर्पित किया परन्तु आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। सम्यक् विचारोपरांत संदर्भित आरोपों की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) के तहत संकल्प ज्ञापांक-2064 दिनांक 06.02.2015 द्वारा श्री प्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन (संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना का पत्रांक-756 दिनांक 15.05.2017) में श्री प्रकाश के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित बताया गया। विभागीय पत्रांक-6226 दिनांक 24.05.2017 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से बचाव बयान/लिखित अभिकथन की माँग की गयी। इस क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 08.06.2017) में श्री प्रकाश ने मुख्य रूप से संचालन पदाधिकारी द्वारा पक्षपात किये जाने एवं उनके बचाव बयान की समीक्षा नहीं किये जाने का उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला पदाधिकारी द्वारा श्री जगनारायण सिंह के आवेदन (जिससे वाद सं०-91/2012-13 उद्भूत हुआ) के निष्पादन हेतु निदेश दिये जाने के आधार पर स्वयं द्वारा पारित आदेश को औचित्यपूर्ण दर्शाया है।

आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रकाश के लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि श्री जगनारायण सिंह के आवेदन में निहित मामला (किराया नहीं देने वालों से दुकान/परिसर खाली कराने हेतु) Bihar Building Control (Lease, Rent & Eviction) Act 1982 से संबंधित एवं व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय था। जबकि आरोपित पदाधिकारी ने भूमि विवाद वाद सं०-91/2012-13 के रूप में इस मामले की सुनवाई आरम्भ कर दी। तत्समय उक्त सुनवाई/क्षेत्राधिकार के विन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय में दायर रीट याचिका के विचाराधीन होने का संज्ञान रहने के बावजूद आरोपित पदाधिकारी ने आनन-फानन में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिनांक 03.12.2012 को आदेश पारित कर दिया। इस आधार पर श्री प्रकाश का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव वर्णित तथ्यों एवं आरोपों की प्रमाणिकता के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत श्री ओम प्रकाश, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-492/11 को निम्नलिखित शास्ति संसूचित की जाती है:-

(i) 02 (दो) वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) प्रोन्नति पर 03 (तीन) वर्षों तक रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से)।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-68/2015, सा०प्र०-8397

संकल्प

11 जुलाई 2017

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री ओम प्रकाश, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-492/11) तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम, रोहतास (सम्प्रति अन्य आरोपों के लिए निलंबित, मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) के विरुद्ध अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए बिहार भूमि सुधार अधिनियम एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल आदेश पारित करने, दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतने इत्यादि का आरोप प्रतिवेदित है (यथा जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-2246 दिनांक 09.06.2016 से प्राप्त आरोप, प्रपत्र 'क' एवं अनुलग्न अभिलेख)।

2. जिला स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि श्री प्रकाश ने भूमि विवाद वाद (अभिलेख संख्या-07/13-14, 09/13-14, 10/13-14 एवं 38/13-14) के निष्पादन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परिपत्रों का उल्लंघन करते हुए व्यवहार न्यायालय की शक्तियों का अतिक्रमण किया। वाद की सुनवाई में उन्होंने सरकार के हितों की अनदेखी की तथा अनाबाद बिहार सरकार की भूमि का गलत ढंग से दखलदार रैयत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-3145 दिनांक 01.03.2016 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में विभागीय पत्रांक-11135 दिनांक 16.08.2016, एवं पत्रांक-12530 दिनांक 14.09.2016 द्वारा स्मारित भी किया गया। तत्पश्चात् श्री प्रकाश ने स्पष्टीकरण (दिनांक 06.06.2017) समर्पित करते हुए आरोपों पर अपना बचाव बयान प्रस्तुत किया, जिसकी समीक्षा के उपरांत मामले के वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

3. अतएव यह निर्णय लिया गया है कि श्री ओम प्रकाश के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की वृहद जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, **विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना** एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा मनोनीत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी होंगे।

4. श्री प्रकाश से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/नि०था०-11-08/2017, सा०प्र०-8300

**संकल्प
7 जुलाई 2017**

श्री प्रभाष कुमार, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-894/11) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो, भोजपुर को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 14.06.2017 को 20,000 (बीस हजार) रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं०-44/17, दिनांक 14.06.2017 धारा-7/13 (2)-सह-पठित धारा-13 (1) (डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के ज्ञापांक-1650, दिनांक 20.06.2017 द्वारा उपलब्ध कराते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (1) (ग) एवं नियम-9 (2) क में निहित प्रावधानों के तहत श्री कुमार को न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 14.06.2017) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में निर्धारित किया जाता है। न्यायिक हिरासत/कारा से मुक्त होने पर भी इनका निलंबन यथावत् रहेगा तथा इसके अनुपालन में ये उक्त निर्धारित मुख्यालय में अपना योगदान करेंगे।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-119/2015, सा०प्र०-7617

**संकल्प
21 जून 2017**

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विनोद कुमार पंकज, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-1147/11) तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरुद्ध कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं महत्वपूर्ण कार्यों को लंबित रखने इत्यादि गम्भीर आरोप जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-102 (मु०) दिनांक 12.12.2015, 248 (मु०) दिनांक 23.12.2015 एवं 2917 दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रतिवेदित है (यथा, अनुलग्न प्रपत्र 'क' में वर्णित)।

2. जिला स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए श्री पंकज से स्पष्टीकरण माँगी गयी। एतद्संबंधी निर्गत विभागीय पत्रांक-2737 दिनांक 07.03.2017 के अनुपालन में श्री पंकज का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ, जिससे अग्रेत्तर कार्रवाई बाधित रही।

3. अतएव यह निर्णय लिया गया है कि श्री पंकज के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की वृहद जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे।

4. श्री पंकज से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-23/2016, सां०प्र०-7618

संकल्प

21 जून 2017

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती नीतू सिंह, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-1268/11) तत्कालीन उप सचिव, बिहार राज्य महिला आयोग, पटना के विरुद्ध प्रभारी उप सचिव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना के दायित्व निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता बरतने इत्यादि का आरोप समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4930 दिनांक 24.11.2016 द्वारा प्रतिवेदित है (यथा, अनुलग्न प्रपत्र 'क' में वर्णित)।

2. समाज कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' गठित किया गया तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1138 दिनांक 31.01.2017 द्वारा श्रीमती सिंह को निलंबित किया गया। विभागीय स्तर पर गठित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-1295 दिनांक 03.02.2017 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में समर्पित स्पष्टीकरण में उन्होंने आरोपों पर अपना बचाव प्रस्तुत किया जिसके उपरांत मामले के वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

3. अतएव यह निर्णय लिया गया है कि श्रीमती नीतू सिंह के विरुद्ध अनुलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की वृहद जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे।

4. श्रीमती सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० कारा/नि०को०(प्रोबेशन)-03-/2017-4035

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

25 जुलाई 2017

श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला प्रोबेशन पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान के विरुद्ध जिलाधिकारी, सीवान के पत्रांक 538 दिनांक 20.07.2017 के द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र प्रतिवेदित किया गया है। आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में प्रतिवेदित है कि T.A No-13/2006 सूचित हलवाई बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय, सीवान के द्वारा पारित आदेश एवं डिक्ली के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील दायर करने हेतु श्री दीप नारायण राय, जी०पी०, सीवान के पत्रांक 61 दिनांक 05.05.2011 के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला विधि शाखा को प्रेषित किया गया था, किन्तु श्री सिंह के द्वारा उक्त महत्वपूर्ण पत्र का पूरे पदस्थापन काल में पूर्ण रूपेण पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जो उनकी घोर लापरवाही एवं अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री विनोद कुमार सिंह, तत्कालीन जिला प्रोबेशन पदाधिकारी, सीवान सम्प्रति प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सासाराम (रोहतास) के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण (छपरा) को संचालन पदाधिकारी तथा प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, सीवान को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सं० कारा/नि०को०(प्रोबेशन)-०१- / 2016-4234

संकल्प

2 अगस्त 2017

श्री कुमार अभिनव, बिहार प्रोबेशन सेवा, तत्कालीन प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित (संलग्न प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेऊर, पटना) के विरुद्ध अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, चुनाव ड्यूटी को नजरअंदाज करने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 155 दिनांक 05.05.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री अभिनव के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4955 दिनांक 12.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1018/भी० दिनांक 26.09.2016 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री अभिनव के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 7495 दिनांक 19.12.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री अभिनव से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री अभिनव के द्वारा दिनांक 16.01.2017 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को निदेशित नहीं किया गया एवं संदर्भित अभिलेख से सम्पुष्ट किए बिना ही उनके अभिकथन को निराकृत कर दिया गया। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (मुख्य परीक्षा) में शामिल होने के लिए जिलाधिकारी से विधान सभा चुनाव से विमुक्त करने का अनुरोध किया था और इस आधार पर जिला पदाधिकारी द्वारा उन्हें मौखिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। संचालन पदाधिकारी द्वारा ऐसे विवक्षित उन्मुक्ति का संज्ञान लिया जाना चाहिए था। श्री अभिनव का कहना है कि पंचायत चुनाव में उन्होंने निर्वाचन कर्तव्य करने का साक्ष्य अभिकथन के साथ संलग्न किया जिसकी सम्पुष्टि जिला निर्वाचन शाखा, मुजफ्फरपुर से की जा सकती थी, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा ऐसे निश्चायक साक्ष्यों को भी नजरअंदाज किया गया एवं बिना तथ्यात्मक सम्पुष्टि के उनके द्वारा आरोप को प्रमाणित मान लिया गया।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री अभिनव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा खुद के चुनाव कार्य से उन्मुक्त होने का किया गया दावा गलत प्रमाणित है एवं इनके द्वारा उक्त अवधि में उपार्जित अवकाश में रहने के दावे के प्रमाणक के रूप में किसी विश्वसनीय आवेदन या स्वीकृत्यादेश के अभाव में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं पत्र तामिला के बावजूद चुनाव कार्य नहीं करने के गठित आरोप प्रमाणित है। आरोपित पदाधिकारी का अवकाश आवेदन न तो स्वीकृत है और न ही कोई अनुशंसा ही उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा भेजी गयी है। दिनांक 10.05.2016 के अपने समर्पित आवेदन में स्थानीय चुनाव संपन्न कराकर इस्तीफा सौंपने के इनके दावे का प्रश्न है तो इनके द्वारा पंचायत चुनाव में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में अपने प्रतिनियुक्ति पत्र का तामिला मोबाईल एवं निबंधित ड्राक से भेजी गयी सूचना के बावजूद भी नहीं किये और नियुक्ति पत्रों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी को वापस किये जाने का तथ्य अभिलेख आधारित है। संकल्प ज्ञापांक 155 दिनांक 05.05.2016 के द्वारा आरोपित पदाधिकारी निलंबित भी हो चुके थे तो ऐसी स्थिति में उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनकी ही सूचना के आधार पर जब उस नियुक्ति पत्र को दिनांक 02.04.2016 के पत्र द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को तामिला नहीं होने की सूचना के साथ वापस किया जा चुका था, तब आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 10.05.2016 को चुनाव कार्य संपन्न कराकर इस्तीफा सौंपने का किया गया दावा पूर्णतया गलत साबित होता है।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अभिनव के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया :-

(i) निंदन की सजा।

(ii) पांच (05) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड।

6. उपर्युक्त विनिश्चयी वृहत दंड "पांच वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड " के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2062 दिनांक 26.04.2017 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 939 दिनांक 24.07.2017 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त " पांच (05) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड " संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार अभिनव, तत्कालीन प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित (संलग्न प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेऊर, पटना) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है :-

(i) निंदन की सजा।

(ii) पांच (05) वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड।

8. इनके निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचानां

28 जुलाई 2017

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0) सीतामढ़ी-11/2016-319501—श्री विनित कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुपरी (सीतामढ़ी) को आर्थिक अपराध इकाई (निगरानी विभाग), पटना की टीम द्वारा दिनांक 02.07.2016 को कथित तौर पर घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 भाग-4 के नियम-(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0-279043 दिनांक 25.07.2016 द्वारा कारा निरोध की तिथि 02.07.2016 से उनके कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

2. श्री सिन्हा के द्वारा दिनांक 21.02.2017 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 22.02.2017 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं0-319468 दिनांक 28.07.2017 द्वारा श्री सिन्हा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में निलम्बनमुक्त कर दिनांक 22.02.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

3. चूँकि श्री सिन्हा के विरुद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है तथा उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा गया जिसके लिए उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0-065/16 दर्ज है। अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री सिन्हा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के आलोक में योगदान की तिथि दिनांक 22.02.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

4. निलम्बन अवधि में श्री सिन्हा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. निलम्बन अवधि में श्री सिन्हा का मुख्यालय समाहरणालय, सीतामढ़ी निर्धारित किया जाता है।

6. निलम्बनादेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा, विशेष-सचिव।

28 जुलाई 2017

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0) सीतामढ़ी-11/2016-319468—श्री विनित कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुपरी (सीतामढ़ी) को आर्थिक अपराध इकाई (निगरानी विभाग), पटना की टीम द्वारा दिनांक

02.07.2016 को कथित तौर पर घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 भाग-4 के नियम- (2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं०- 279043 दिनांक 25.07.2016 द्वारा कारा निरोध की तिथि 02.07.2016 से उनके कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया।

2. श्री सिन्हा दिनांक 21.02.2017 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 22.02.2017 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया।

3. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री सिन्हा को निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक 22.02.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

4. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधा किशोर झा, विशेष-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>